बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 251 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 24 जुलाई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागारिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

संसद मार्च में प्रदर्शनकारी को लगीं 'पैलेट' जैसी चोटें? परिजनों के दावों के बीच दिल्ली पुलिस ने किया खंडन

नई दिल्ली । 'संसद मार्च' के दौरान घायल एक प्रदर्शनकारी के शरीर पर पैलेट जैसी चोटों के दावे के बाद पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर विवाद गहरा गया है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती प्रदर्शनकारी के परिजनों और कुछ अस्पताल सूत्रों का दावा है कि सर्जरी के दौरान उसके शरीर से कई पैलेट जैसी वस्तुएं निकाली गईं, जबकि गर्दन के पास फंसी एक वस्तु को रक्त वाहिका के निकट होने के कारण नहीं निकाला जा सका। प्रदर्शनकारी के चेहरे, गर्दन और सीने पर कई गोलाकार चोटों के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। घायल प्रदर्शनकारी के स्वजन का आरोप है कि घटना के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के एक जवान की ओर से पैलेट गन चलाई गई, जिससे यह चोटें आईं।

नीट पेपर लीक और शिक्षा संकट पर कांग्रेस आक्रामक, रणदीप सुरजेवाला ने राज्यसभा में दिया नियम 267 के तहत नोटिस

नई दिल्ली । संसद के मानसून सत्र के दौरान नीट प्रश्नपत्र लीक मामला और छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुँच गई है। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में सभी तय कामकाज को स्थगित कर देश की परीक्षा प्रणाली में व्याप्त संस्थागत संकट पर तत्काल चर्चा कराने के लिए नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। सुरजेवाला ने अपने नोटिस में कहा है कि सदन शून्यकाल, प्रश्नकाल और दिन के अन्य सभी निर्धारित कार्यों को रोककर भारत की पूरी परीक्षा प्रणाली में उपजे इस गंभीर संकट पर प्राथमिकता से चर्चा करे। उन्होंने जोर देकर कहा कि नीट परीक्षा रद्द होने से बाईस लाख से अधिक अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है, जिससे छात्रों में भारी अनिश्चितता और असंतोष का माहौल है। उन्होंने कहा, ''यह सदन शून्यकाल तथा प्रश्नकाल और दिन के अन्य निर्धारित कार्यों से संबंधित नियमों को स्थगित कर भारत की परीक्षा प्रणाली में व्याप्त संस्थागत संकट पर तत्काल चर्चा करे।'' राज्यसभा सदस्य सुरजेवाला ने कहा कि यह चर्चा विशेष रूप से इसलिए आवश्यक है क्योंकि संगठित प्रश्नपत्र लीक गिरोह संबंधी आरोपों के बाद राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा- स्नातक (नीट-यूजी) 2026 परीक्षा रद्द करनी पड़ी, जिससे 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कम से कम 65 भर्ती

परीक्षाओं में बार-बार प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं ने यह उजागर किया है कि वैधानिक सुरक्षा उपायों के बावजूद व्यवस्था संबंधी खामियां अब भी बनी हुई हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' (ओएसएम) प्रणाली के क्रियान्वयन में गंभीर कमियों के कारण मूल्यांकन, पारदर्शिता और प्रक्रियागत निष्पक्षता को लेकर व्यापक शिकायतें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि इससे लाखों छात्रों को शैक्षणिक, आर्थिक और मानसिक स्तर पर गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले पांच वर्षों में नीट से जुड़े कम से कम 93 छात्रों द्वारा आत्महत्या किए जाने की खबरें सामने आई हैं। उन्होंने अपने नोटिस में यह भी कहा कि जवाबदेही तय करने और सुधारों की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और अभिभावकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की खबरें आई हैं। उनके अनुसार, परीक्षाओं और सार्वजनिक भर्ती प्रक्रियाओं की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। सुरजेवाला ने कहा, ''इन गंभीर चिंताओं को देखते हुए इस विषय पर सदन में तत्काल विचार और चर्चा की आवश्यकता है।'' यह नोटिस ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस ने संसद में सभी कामकाज स्थगित कर नीट प्रश्नपत्र लीक, छात्रों के आंदोलन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराने की मांग की है। सरकार ने कहा है कि वह नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि राज्यसभा में यह चर्चा नियम 267 तथा लोकसभा में नियम 56 के तहत करायी जाए। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण पहले तीन दिनों के दौरान संसद के दोनों सदनों में कोई कामकाज नहीं हो सका।

दिल्ली प्रोटेस्ट में विदेशी फंडिंग? याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तुरंत सुनवाई के लिए भरी हामी

नई दिल्ली दिल्ली में सोमवार (20 जुलाई) को कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर भारी संख्या में छात्र शांतिपूर्ण 'चलो संसद' मार्च में शामिल हुए थे. नीट पेपर लीक में जवाबदेही की मांग कर रहे स्टूडेंट्स पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था जिसमें कई बच्चे घायल हुए थे. झड़प में कई पुलिसवालों को भी चोट आई थी, जिसके बाद दावा किया गया कि इस प्रदर्शन में विदेशी फंडिंग की गई है और अराजक तत्वों ने छात्रों के प्रदर्शन पर कब्जा कर लिया है. ऐसी याचिका जब हाई कोर्ट के पास पहुंची, तो कोर्ट ने इस मामले में तुरंत सुनवाई के लिए हामी भर दी. दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है, उसमें दावा किया गया है कि यह आंदोलन विदेशी फंडिंग पाने वाले संगठनों और कुछ राजनीतिक तत्वों की बड़ी साजिश का हिस्सा था. इसी के साथ मामले में छह्ह की जांच की मांग की गई है. अब हाईकोर्ट कल (शुक्रवार, 24 जुलाई) इस जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा. याचिका में ये भी आरोप हैं कि मार्च के दौरान हिंसा हुई, लोगों की आवाजाही रोकी गई, पत्रकारों पर हमला हुआ, सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया. ये भी आरोप हैं कि संसद की सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की गई और कई पुलिसकर्मी घायल हुए. यह जनहित याचिका सतीश कुमार अग्रवाल ने दाखिल की है. इससे पहले 21 जुलाई को जब छात्रों पर हुई पुलिस बर्बरता का दावा करते हुए याचिका दायर की गई थी और तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी तब हाई कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में कोर्ट को न घसीटें. कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से मना कर दिया था, लेकिन मामले को अगली तारीख यानी 22 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया था. फिर 22 जुलाई को लाठीचार्ज की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसी बेंच ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर जवाब मांगा. सरकार और पुलिस को अपना जवाब चार हफ्ते के अंदर दाखिल करना होगा. साथ ही, कोर्ट ने आंदोलन के सीसीटीवी और पुलिस बॉडी कैम के फुटेज सुरक्षित रखने के लिए भी कहा. अगली सुनवाई 11 सितंबर तय की गई है.

पीएम मोदी के एलान पर सीजेपी का पलटवार: कहा- मरहम नहीं, पेपर लीक रोकने की व्यवस्था चाहिए; शिक्षा मंत्री दें इस्तीफा

नई दिल्ली ।

नीट-यूजी पेपर लीक विवाद और छात्रों के विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और दोषियों को जल्द सख्त सजा दिलाने की घोषणा की। इस पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पेपर लीक के मूल कारणों पर सवाल उठाए। आशुतोष रांका ने कहा कि पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं

क्योंकि व्यवस्था में नाकाबिल लोग बैठे हैं। उन्होंने जिम्मेदारी तय करने और दोषियों के मन में डर पैदा करने की बात कही। रांका ने व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया ताकि पेपर लीक की गुंजिश न रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक एक संगठित गिरोह के जरिये होता है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक कई लोग शामिल होते हैं और आर्थिक लाभ उठाते हैं। रांका ने कहा कि केवल कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था को बदलना जरूरी है। उन्होंने पीएम के एक्स पोस्ट पर

टिप्पणी की कि यह चोट लगने के बाद मरहम लगाने जैसा है। उनकी लड़ाई चोट लगने के कारणों को लेकर है।

सीजेपी की मांगें और आरोप

आशुतोष रांका ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। उन्होंने बताया कि देश में कई बड़े मामलों में ऐसे कोर्ट बने, पर मूल समस्या खत्म नहीं हुई। सरकार ने मूल कारणों और व्यवस्था से जुड़ी खामियों को दूर नहीं किया। रांका ने शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं की जड़ अक्षमता और भ्रष्टाचार को बताया। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय तक जाती है। रांका ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक अपना आंदोलन जारी रखने की घोषणा की।

छात्रों और प्रदर्शनकारियों की प्रतिक्रिया

जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे छात्रों और प्रदर्शनकारियों ने भी प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया दी। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री को सबसे पहले छात्रों की आवाज सुननी चाहिए। लाखों युवा सड़क पर हैं, पर उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारी ने शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कही और बातचीत से समाधान की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें आंदोलन का रास्ता बदलने पर मजबूर न किया जाए। एक अन्य छात्र ने संसद मार्च के दौरान लाठीचार्ज और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया।

स्थायी समाधान की आवश्यकता

प्रदर्शनकारियों ने सरकार से इस पूरे मामले का स्थायी समाधान निकालने की मांग की। उन्होंने केवल मुद्दे को दबाने की कोशिश न करने की बात कही। एक प्रदर्शनकारी ने प्रधानमंत्री से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने को कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री से जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया, न कि केवल सामाजिक मंच पर बयान देने पर। एक युवक ने कहा कि केवल एक्स पोस्ट करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने जमीन पर कार्रवाई की आवश्यकता बताई। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा कि सरकार के वास्तविक कदम बयान से ज्यादा जरूरी हैं। उन्होंने ठोस कार्रवाई देखने की इच्छा व्यक्त की।

17 मेट्रो स्टेशन बंद, इंटरनेट पर रोक; फिर भी कैसे लगातार जंतर-मंतर पर बढ़ रही भीड़?

नई दिल्ली । जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बीच गुरुवार सुबह धरनास्थल पर रात की तुलना में भीड़ अपेक्षाकृत कम दिखाई दी। जंतर-मंतर, जनपथ और आसपास के क्षेत्रों में प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी करते रहे, हालांकि पूरे इलाके में स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही। कहीं भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव, धक्का-मुक्की या टकराव की स्थिति देखने को नहीं मिली। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, जंतर-मंतर के आसपास इंटरनेट सेवाएं प्रभावित होने और आसपास के 17 मेट्रो स्टेशनों पर पाबंदियों का असर सुबह के समय लोगों की आवाजाही पर दिखाई दिया।

सुबह ही जंतर-मंतर पहुंची हुमा कुरैशी

इसके बावजूद प्रदर्शनकारी अलग-अलग मार्गों से पैदल ही धरनास्थल की ओर पहुंचते रहे। कई लोग जनपथ और आसपास के क्षेत्रों से पैदल मार्च करते हुए जंतर-मंतर पहुंचे और प्रदर्शन में शामिल हुए। सुबह के समय धरनास्थल पर अभिनेत्री हुमा कुरैशी भी अपने साथियों के साथ पहुंचीं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और कुछ समय तक धरनास्थल पर मौजूद रहीं। उनके पहुंचने पर वहां मौजूद लोगों में हलचल बढ़ गई। धरनास्थल और उसके आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम बने हुए हैं। पुलिस लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है, जबकि प्रदर्शनकारी निर्धारित क्षेत्र में नारेबाजी और प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। सुबह के समय भीड़ का दबाव रात की तुलना में कम जरूर रहा, लेकिन प्रदर्शन लगातार जारी है और समय बीतने के साथ लोगों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती दिखाई दे रही है। जंतर मंतर और उसके आसपास के मेट्रो स्टेशन बंद होने पर प्रदर्शनकारी जो इस क्षेत्र के सबसे नजदीक मेट्रो स्टेशन या अन्य जो स्टेशन चालू हैं या अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उनसे वहां पहुंच रहे हैं। या फिर लोग पैदल ही धरना स्थल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं।

किसानों का जत्था भी पहुंचा जंतर-मंतर

किसानों का जत्था भी वहां पर पहुंचा हुआ है या किस हरी टोपी लगाए हुए हैं और उन पर भर्ती किसान यूनियन लिखा हुआ है। लगातार नारेबाजी चल रही है और भीड़ अब फिर से धीरे-धीरे कर बढ़ रही है। बड़ी संख्या में युवतियां भी पहुंची हुई हैं।

'हमेशा देर कर देता हूं...', शशि थरूर ने उर्दू शायर मुनीर नियाजी के शेर से कसा पीएम मोदी पर तंज

नई दिल्ली । कांग्रेस के सीनियर नेता शशि थरूर ने गुरुवार को पेपर लीक मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया पर शायरी के जरिए तंज कसा। उन्होंने पाकिस्तानी उर्दू शायर मुनीर नियाजी के एक मशहूर शेर का इस्तेमाल करते हुए कहा कि सरकार का जवाब बहुत देर से आया है। देश के युवाओं के भविष्य और कल्याण की सुरक्षा के मकसद वाली प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया पर तंज करते हुए तिरुवनंतपुरम के सांसद ने एक्स पर पोस्ट किया, 'हमेशा देर कर देता हूं मैं हर काम करने में, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो। ' इस शेर के जरिए थरूर ने केंद्र सरकार की देरी की आलोचना की। इस तरह का पोस्ट करके तिरुवनंतपुरम के सांसद ने केंद्र पर

निशाना साधने में कांग्रेस के अन्य नेताओं का साथ दिया और अपनी आलोचना के लिए शेर का सहारा लिया। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक विवाद पर सीधे छात्रों से बात की, कई उपायों की घोषणा की और दोषियों को कड़ी सजा देने का वादा किया। पीएम मोदी ने लिखा, 'हमारे युवाओं की भलाई और भविष्य से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है! हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है। संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। यह छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे हमारे कदमों की कड़ी का ही एक हिस्सा है। ' प्रधानमंत्री ने आगे कहा, 'जो लोग हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ' इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन एक महीने से ज्यादा समय से जारी है, जबकि वैज्ञानिक और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल गुरुवार को 26वें दिन में प्रवेश कर गई।

सम्पादकीय...

जग मुआ...

थैंक यू मोदी जी, सोनम वांगचुक की जान बचाने के लिए। वर्ना कांकरोजों ने तो बेचारे लद्दाखी की जान ही ले ली थी। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, पूरे बीस दिन बेचारे पहाड़ी को भूखा रखा। वह भी दिल्ली की भयंकर गर्मी में। वह भी जंतर-मंतर पर खुले आसमान के नीचे। ऊपर से जब-तब बारिश और। साथ में कई छात्रों को और भूख हड़ताल पर बैठा दिया यानी बंदा उठना भी चाहे तो भी शर्मो-शर्मी बैठा रहे। बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे रहें और बुजुर्ग भूख की मार से उठ जाए, तो लोग क्या कहेंगे? इसी चक्कर में बेचारे की जान पर ही बन आयी थी। वैसे आप जी ने धीरज भी खूब दिखाया। दिल्ली में ऐन अपने सेवा तीर्थ की नाक के नीचे, कांकरोजों को चार-चार हफ्ते जमा रहने दिया। जिंदाबाद-मुर्दाबाद करने दिया। धर्मेंद्र बाबू का इस्तीफा मांगते रहने दिया। और भी न जाने क्या-क्या मांगते रहने दिया। तीन-तीन हफ्ते तक भूखे रहने दिया। 145 करोड़ के चुने हुए पीएम ने पूरे बीस दिन तक इंतजार किया। वह तो जब वांगचुक के भूखे रहने का इक्कीसवां दिन लग गया, तो आप जी ने झट पहचान लिया कि अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर क्या था, छेड़ दिया ''ऑपरेशन प्राण रक्षा''शाह जी की पुलिस ने भी झटपट कार्रवाई की। मोदी सरकार की पुलिस है, कोई पिछले जैसी लटकाने, अटकाने, भटकाने वाली, सरकारों वाली पुलिस थोड़े ही है, जो देर लगाती। सुबह तड़के ही जंतर-मंतर पर धावा बोल दिया। कैमरों को रोकने के लिए टेंपरेरी पर्दा खड़ा किया, कांकरोजों को धकिया के दूर भगाया, वांगचुक को टांगाटोली कर के उठाया, एंबुलेंस में डाला और सीधे अस्पताल पहुंचा दिया। इसके बाद, भूख हड़ताल करने वालों की जान बचाने के लिए क्या करना होता है, वह भारत के पुलिस वाले बखूबी जानते हैं। अंग्रेजों के जमाने में उनके पुरखों ने बार-बार ऐसे ही प्राण रक्षा करने का काम किया जो था। उनकी आदत का असर पुलिस की अब की पीढ़ियों के खून में है। और कुछ हो न हो, वांगचुक की जान अब कांकरोजों की वजह से भूखे रहने से नहीं जाएगी। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि मोदी जी आप सोनम वांगचुक की जान की कुछ ज्यादा ही परवाह करते हैं। अभी पिछले साल ही तो लद्दाख वाले झंझट के टैम पर भी वांगचुक की जान बचायी थी। अगले को एनएसए में गिरफ्तार करना पड़ा तो किया, उदयपुर की जेल में बंद रखना पड़ा तो रखा, पर अगले की जान बचाकर मानी। और सात-आठ महीने बाद, जब खतरा टल गया तो अगले को बिना कोई आरोप लगाए, जेल से बाहर भी कर दिया। हमें तो लगता है कि आप जी के इस तरह बार-बार जान बचाने ने ही सोनम वांगचुक को सिर चढ़ा दिया है। बंदा बार-बार अपनी जान जोखिम में डाल देता है कि आप जी तो बचा ही लोगे। ये फुनसुक वांगडू आप की ममता का बेजा फायदा उठा रहा है, जी। और आप जी हैं कि उसे बेजा फायदा उठाने देते हैं। फिर आप जी अगर ऑपरेशन प्राण रक्षा चला ही रहे थे, तो वांगचुक की ही तरह, बगल में ही भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को भी उठवा लेते, उनकी भी प्राण रक्षा कर देते। कम से कम विरोधियों को यह प्रचार करने का मौका नहीं मिलता कि मोदी को छात्रों की परवाह नहीं है--बच्चों को ही मरने को छोड़ दिया। अब शाह जी की पुलिस इतनी कमजोर तो नहीं है कि वह सकती कि जंतर-मंतर से वांगचुक के साथ तीन-चार भूख हड़ताली छात्रों को भी नहीं उठा पाती। वैसे इतना तो हम भी समझते हैं कि ये छात्र वगैरह हैं तो इसी तरह के सलूक के काबिल। चार किताबें क्या पढ़ गए, हर बात पर बहस करना चाहते हैं, हर चीज पर सवाल और वह भी आप जी से। अब इन्हें कौन समझाए कि आप जी ने सवाल करना तो उन मीडिया वालों का भी छुड़वा दिया, जिन्हें तनख्वाह ही सवाल करने की मिलती थी, फिर ये बच्चे किस खेत की मूली हैं। मगर ये नहीं समझते। पढ़ाई रुकवा दो फिर भी नहीं समझते। जेल में डाल दो फिर भी नहीं समझते। आप जी के मास्टर स्ट्रोक तक को मास्टर स्ट्रोक नहीं समझते हैं, उल्टे विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं--जाहिल कहीं के। अब आप इनकी सुनने लगें तब तो हो चुकी इस महान देश की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा की वापसी। इन्हें बाबरी मस्जिद तो अब भी याद है, पर संत कबीरदास जी की इतनी पुरानी शिक्षा बिल्कुल ही भूल गए हैं। और आप जी की सरकार कबीरदास जी की शिक्षा पर चल रही है, तो ये उसका भी विरोध कर रहे हैं। कबीरदास जी ने तो मुगलों के टैम में कह दिया था--''पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, भया न पंडित कोइ''। कहने को तो आपजी से पहले वालों ने इसे बच्चों की किताबों में रखा था, रटवाया भी था, पर इस पर चलना नहीं सिखाया था। तभी तो आजादी के बाद से देश कबीरदास जी की शिक्षा से उल्टे रास्ते पर ही चलता रहा। पोथियां कम थीं, पढ़ने की समझ भी लोगों की कम थी, फिर भी गरीब-गुरबा के बीच यह धारणा फैल गयी कि पढ़ेंगे बच्चे, तभी आगे बढ़ेंगे बच्चे! और तो और जब इस चीज में बाजार आ गया, तो पढ़ाने के धंधे से खूब कमाई भी होने लगी, पर कबीर की शिक्षा पीछे छूटती गयी। आपजी का ही राज है जो सचमुच कबीरदास जी की शिक्षा का अनुसरण कर रहा है--पोथी पढ़ने से कोई पंडित नहीं हो जाता, तो ये पढ़ाई का खेल ही क्यों रहे? पर नेहरू जी के टैम से पड़ी गयी की आदत आसानी से कहां छूटती है। आपने कहा भी कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, जिसके लिए पढ़ने की भी जरूरत नहीं है--पर किसी पर कुछ असर पड़ा? फिर खबर आयी कि आप के राज में करीब एक लाख सरकारी स्कूल बंद करा दिए। फिर खबर आयी कि करीब दो करोड़ बच्चों का स्कूल में दाखिला होना कम करा दिया। आपके सबसे प्रिय राज्य में 45 फीसद से ज्यादा बच्चों को बारहवीं से पहले-पहले पढ़ाई के चक्कर से आजाद करा दिया। शिक्षा पर खर्च हर साल घटा दिया। शिक्षा पर पूरी तरह से आरएसएस का कब्जा करा दिया। बारह साल में 185 परीक्षाओं का पेपर लीक करा दिया। और सुनते हैं जल्द ही यूनीवर्सिटी नाम की दुकान बंद कराने की तैयारी है। यानी सरकार लोगों को समझाने की हरचंद कोशिश कर रही है कि कबीरदास जी के रास्ते पर चलो, पोथी पढ़ना छोड़ दो! पर आम जन है कि मानता ही नहीं है। प्राचीन गौरव की पुनर्स्थापना के लिए सरकार को अब और कड़े कदम उठाने ही होंगे। जैसे आजम खान की बनायी अली जौहर यूनिवर्सिटी की कुल चालीस में अट्ठाइस इमारतों को ढाना। बख्तियार खिलजी का बदला भी और कबीर की शिक्षा पर अमल भी। और हां! धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हर्गिज नहीं होगा।

मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता

मध्य प्रदेश के यूसीसी विधेयक में लैंगिक समानता को प्रमुख आधार माना गया है। सम्पत्ति, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और पारिवारिक अधिकारों से जुड़े मामलों में महिलाओं को समान कानूनी दर्जा देने की दिशा में प्रावधान किए गए है। गुजरात और उत्तराखंड की ही तरह मध्य प्रदेश में भी आदिवासी समाज को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। क्योंकि उनकी परम्पराएं बहुत अलग है। एक समान कानून लागू करने के लिए मध्य प्रदेश की पहल सराहनीय है।

मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस तरह उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला मध्य प्रदेश चौथा राज्य बन गया है। अब राज्य में राम से लेकर रहीम तक सभी के लिए एक समान कानून लागू होगा और तुष्टिकरण और पर्सनल लॉ के युग का अंत होगा। इस विधेयक के जरिये अब कोई भी व्यक्ति पहली पत्नी या पति के जीवित रहते दूसरा विवाह नहीं कर पाएगा। तीन तलाक और निकाह हलाला को पूरी तरह से गैर कानूनी और दंडनीय बना दिया गया है। तलाक केवल कोर्ट के जरिये ही मान्य होगा। लिव-इन में रह रहे जोड़ों को एक माह के भीतर रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण कराना होगा। विधेयक को राज्यपाल के जरिये राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कानून लागू होने के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन, नौकरी के रिकार्ड और सम्पत्ति से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किए जाने से मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा किया गया वादा भी पूरा हो गया। भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ काल से ही तीन चुनावी मुद्दे रहे। इनमें श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 और समान नागरिक संहिता। राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किया जा चुका है। केन्द्र की मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक को भी खत्म कर दिया है। अब भाजपा शासित राज्य एक के बाद एक समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की ओर अग्रसर है। समान नागरिक संहिता (यूनिवर्सल सिविल कोड) का मुद्दा कोई नया नहीं है। आजादी के बाद से ही इसको लेकर विवाद होते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी समय-समय पर देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की जरूरत पर जोर दिया है। 1835 में ब्रिटिश शासन के दौरान पहली बार भारतीय कानूनों में एकरूपता लाने का विचार सामने आया था। अंग्रेजों ने आपराधिक और प्रशासनिक कानूनों में तो एकरूपता स्थापित की लेकिन विवाह उत्तराधिकार और धार्मिक मामलों को समुदायों के पर्सनल लॉ के अधीन रखा। शाह बानो से लेकर सायरा बानो तक के मामलों के बाद भी समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग उठी थी लेकिन तत्कालीन केन्द्र की सरकारों ने मुस्लिम वोट बैंक की खातिर कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सत्ता में आते ही समान नागरिक संहिता को राजनीति नहीं राष्ट्र नीति का विषय बताया था और कहा था कि जब एक घर दो कानून से नहीं चल सकता तो एक देश कैसे चल सकता है। समान नागरिक संहिता का अर्थ है, देश के हर नागरिक पर एक समान कानून लागू होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। अभी देश में अलग-अलग मजहबों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ हैं, लेकिन समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद सभी मजहबों के लोगों को एक जैसे कानून का पालन करना पड़ेगा। हमारे देश में अभी धर्म और परंपरा के नाम पर अलग-अलग नियमों को लागू करने की छूट है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए नियम एक-समान होंगे। वैसे इसके लागू होने से नागरिकों के खानपान, पूजा-इबादत, वेशभूषा आदि धार्मिक परंपराओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुस्लिम समाज पुरजोर विरोध करता रहा है। जब 1951 में डॉ. बी.आर. अंबेडकर और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू समाज के लिए हिंदू कोड बिल लाने की कोशिश की थी, तब भी उसके खिलाफ आवाजें थीं। साथ ही केवल एक धर्म विशेष के लिए ऐसा कानून लाने पर सवाल भी उठाए गए थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वालों का तर्क है कि इसके द्वारा सभी धर्मों पर हिंदू कानून लागू कर दिया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे अपने अधिकारों का हनन और धार्मिक परंपराओं पर हमला बताया। संविधान के अनुच्छेद 44 में देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून बनाने की बात की गई है। सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह पंथ, क्षेत्र और भाषा से संबंधित बंटवारा करने वाले आधारों की परवाह किए बिना सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए लेकिन इस पवित्र मंशा को हउव्वा बना दिया गया। एक समान कानून लागू करने की पहल तो मोदी सरकार के शासन में ही हुई। हालांकि समय-समय पर संविधान निर्माताओं और सुप्रीम कोर्ट ने यह महसूस किया कि मुस्लिम महिलाओं के तलाक और भरण-पोषण से जुड़े मुद्दों का संबंध पूजा पद्धति से नहीं बल्कि इसका संबंध इंसानियत से है। इसलिए मुस्लिम महिलाओं से भी इंसाफ होना चाहिए। मध्य प्रदेश के यूसीसी विधेयक में लैंगिक समानता को प्रमुख आधार माना गया है। सम्पत्ति, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और पारिवारिक अधिकारों से जुड़े मामलों में महिलाओं को समान कानूनी दर्जा देने की दिशा में प्रावधान किए गए है। गुजरात और उत्तराखंड की ही तरह मध्य प्रदेश में भी आदिवासी समाज को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। क्योंकि उनकी परम्पराएं बहुत अलग हैं। एक समान कानून लागू करने के लिए मध्य प्रदेश की पहल सराहनीय है।

सरकार की मिलावट को मिलावट नहीं सम्मिश्रण कहिए जनाब

एक राजा था। अब राजा ऐसा ही था जैसे राजा होते हैं। दिन भर चापलूसों से घिरे रहना, हर समय हम हम करना और दिन में कम से कम चार बार कपड़े बदलना। राजा का यही काम था। इसी काम में वह दिन के अठारह बीस घंटे बिता देता था। हाँ, इन सब कामों के अतिरिक्त वह भजन पूजा में भी बहुत सारा समय बीतता था। मतलब सबकुछ मिला कर वह पूरा दिन आराम से बिता देता था। राजा जब कभी अपने देश में बोर होता तो किसी और देश में घूम आता। उस देश में भी खूब मौज मस्ती होती। शाही सत्कार, राजकीय सम्मान, नाच गाना, खाना पीना, मतलब सब कुछ होता। हाँ, वहाँ से कोई मैडल वैडल भी ले आता। तो राजा के दिन इस तरह आराम से गुजर रहे थे। इन सब कामों से समय मिलता तो राजा राजकाज की भी सोचता था। जब राजकाज सूझता था तो राजदरबार सजता था। राजदरबार होता तो राजा का था पर उसमें वह आता कम ही था। उसके नवरत्न ही कामकाज सम्हालते थे। वह जब भी आता था तो या तो हंसी ठिठोली में ही लगा रहता था या फिर पुराने राजाओं की बुराई में। तो इस तरह से राजा के दिन बड़े अच्छे गुजर रहे थे। एक बार राजा के राज में अकाल पड़ा। हुआ यह कि जिस देश से अन्न आता था, वहाँ युद्ध छिड़ गया। आने जाने के रास्ते बंद हो गए। जिन गाड़ियों से अन्न आता था, वे जहाँ थीं, वहीं रुक गईं। राज्य में अनाज का संकट पड़ गया। ऐसे में राजा ने अपने राजदरबार की बैठक बुलाई। बैठक वैसे ही शुरू हुई, जैसे शुरू होनी चाहिए थी। सारे राजदरबारी आ गए, नवरत्न भी पधार गए। उसके बाद परम्परा का निर्वाह करते हुए, दरबारी ने हुंकार लगाई- गौतमी मित्र, पद्मपुत्र, चौकीदार श्री, श्री 1008, नॉन बायोलॉजिकल, श्री मछंदरनाथ जी महाराज, मास्टर इन इंटायर पोलिटिकल साइंस, पधार रहे हैं sss !!! आत्म प्रशंसा और पुराने राजाओं की फजीहत के बाद राजदरबार का काम शुरू हुआ। अनाज के वजीर ने उठ कर कहा, हे राजाओं के राजा, पूरे विश्व के गुरु, समस्या यह है कि देश में अनाज की कमी हो रही है। जिस रास्ते से हमारे यहाँ अनाज आता है, उस रास्ते पर युद्ध के कारण आवागमन बंद है। तो अनाज की, गेहूं, चावल और दालों की कीमत बढ़ा दो, राजा को हर समस्या का उपाय कीमत बढ़ाना लगता था। और राज्य की धर्मभीरू प्रजा भी धार्मिक राजा के हर जुल्म को सहने के लिए तैयार बैठी थी। पर महाराज, उससे अन्न की कमी तो पूरी नहीं होगी। प्रजा खायेगी क्या? अनाज मंत्री ने डरते डरते कहा। राजा कहना चाहता था, मशरूम खा लेगी, बादाम, काजू और अखरोट खा लेगी पर कुछ पुरानी बात सोच कर चुप रहा। एक दूसरे मंत्री ने, जिसका अनाज मंत्रालय से दूर दूर का कोई संबंध नहीं था और जिसके बेटों ने पत्थर काटने की मशीन लगाई हुई थी, बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मेरे मन में एक विचार आया है। क्यों ना हम अनाज में पत्थर मिला दें। पत्थर सस्ता भी होता है और अनाज में मिलाया भी जाता है। मेरे बेटों की पत्थर की फैक्ट्री है। वे ऐसे पत्थर बनाएंगे कि प्रजा को अनाज में पत्थर का पता भी नहीं चलेगा। विचार तो अच्छा है पर जरा देखना पत्थर ऐसे हों कि अनाज में ऐसे घुल मिल जाएं जैसे दूध में पानी मिल जाता है। पेट्रोल में एथेनॉल मिल जाती है। किसी को पता भी नहीं चलता है और नुकसान भी भरपूर होता है,राजा जी ने कहा। वैसे भी हम यह काम प्रजा को बता कर ही करेंगे। प्रजा को ठगने में मजा तभी है जब उसको बता कर ठगा जाए। राजन, हम सबकुछ प्रजा को बता कर ही करेंगे। इसे मिलावट नहीं, सम्मिश्रण का नाम देंगे। सम्मिश्रण मतलब सरकारी मिलावट।

सड़क से संसद तक बढ़ते राजनीतिक संघर्ष के बीच भारतीय लोकतंत्र के सामने नई चुनौती -समग्र व्यापक विश्लेषण

वैश्विक स्तरपर भारत का लोकतंत्र अपनी सबसे बड़ी शक्ति जनता की भागीदारी, असहमति के सम्मान और शांतिपूर्ण विरोध की परंपरा से प्राप्त करता है।किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में धरना,प्रदर्शन, सत्याग्रह और जनआंदोलन केवल विरोध के साधन नहीं होते,बल्कि वे शासन और जनता के बीच संवाद स्थापित करने के संवैधानिक माध्यम भी माने जाते हैं। भारत की सभ्यता में भी अहिंसक प्रतिरोध की परंपरा अत्यंत प्राचीन रही है,जिसे आधुनिक युग में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसक आंदोलन के रूप में विश्व के सामने स्थापित किया।स्वतंत्रता संग्राम से लेकर किसानों,मजदूरों,छात्रों, महिलाओं और सामाजिक संगठनों तक,शांतिपूर्ण आंदोलनों ने समय-समय पर सरकारों को जनभावनाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित किया।यही लोकतंत्र की आत्मा है कि सरकार और विपक्ष दोनों जनता के प्रति जवाबदेह रहें तथा मतभेदों का समाधान संविधान और संवाद के माध्यम से खोजें। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि समय के साथ-साथ आंदोलन की प्रकृति में उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई देने लगा है। आज अनेक अवसरों पर यह धारणा बनती जा रही है कि कई आंदोलन जनहित और नीति-सुधार से अधिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और दलगत हितों के इर्द-गिर्द केंद्रित हो गए हैं। जनता के एक वर्ग में यह प्रश्न उठने लगा है कि क्या धरना-प्रदर्शन अब लोकतांत्रिक विमर्श का माध्यम रह गए हैं,अथवा वे राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का उपकरण बनते जा रहे हैं? यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संसद जैसी सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच के समानांतर सड़क पर संघर्ष की राजनीति बढ़ती दिखाई दे रही है।इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2026 का मानसून संसद सत्र विशेष चर्चा का विषय बन गया है। 20 जुलाई से प्रारंभ हुए संसद सत्र के साथ ही विभिन्न विपक्षी दलों ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति अपनाई।यूजीसी-नेट,शिक्षा व्यवस्था,छात्रों के मुद्दे,कथित पुलिस कार्रवाई तथा शिक्षामंत्री से इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने संसद के भीतर और बाहर दोनों स्थानों पर आक्रामक रुख अपनाया, दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी आंदोलन को व्यापक राजनीतिक समर्थन मिलने लगा,जिसमें विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं की भागीदारी ने इसे केवल एक छात्र या सामाजिक आंदोलन न रहने देकर राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बना दिया।अब धरना स्थल पर भगदड़, पीएम के आवास पर धरना, फिर 22 जुलाई 2026 को सत्ताधारी पार्टी द्वारा भी आंदोलन धरना व तेलंगाना में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की झड़प यह सब मीडिया में आ रहा है जिसे जनता, मतदाता व पूरा विश्व देख रहे हैं। साथियों इसी क्रम में पर्यावरण कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आंदोलन को भी विपक्ष ने समर्थन दिया। उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की गई और न्यायालय के सुझाव के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे आंदोलन को मानवीय और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से व्यापक चर्चा मिली। लोकतंत्र में किसी भी नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है,किंतु जब ऐसे आंदोलनों के साथ राजनीतिक दल खुलकर जुड़ते हैं तो आंदोलन का स्वरूप स्वतः व्यापक राजनीतिक बहस का विषय बन जाता है। सरकार इसे राजनीतिकरण कहती है, जबकि विपक्ष इसे लोकतांत्रिक समर्थन बताता है। दोनों पक्षों के अपने-अपने तर्क हैं, किंतु अंतिम निर्णय जनता की लोकतांत्रिक समझ पर ही सटीकता से निर्भर करता है। साथियों, इन घटनाओं के समानांतर संसद के भीतर भी लगातार हंगामा, नारेबाजी, स्थगन और बहिर्गमन जैसी स्थितियां देखने को मिलीं।संसद का प्रत्येक मिनट राष्ट्रीय संसाधनों,करदाताओं के धन और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व से जुड़ा होता है। जब 25 दिन के निर्धारित संसदीय सत्र का बड़ा हिस्सा व्यवधानों में व्यतीत होता है,तबस्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या जनहित से जुड़े विधेयक, आर्थिक सुधार, सामाजिक कल्याण और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर्याप्त चर्चा प्राप्त कर पाएंगे?लोकतंत्र में विपक्ष का दायित्व सरकार से कठोर प्रश्न पूछना है, वहीं सरकार का दायित्व उत्तर देना और संसद चलाना है। यदि दोनों पक्ष संवाद के स्थान पर केवल टकराव का मार्ग अपनाते हैं तो अंततः नुकसान सटीकता से जनता का होता है।

साथियों, स्थिति तब और अधिक गंभीर दिखाई दी जब संसद के बाहर पीएम के आधिकारिक आवास के निकट प्रमुख विपक्षी पार्टी द्वारा धरना-प्रदर्शन किया गया।प्रदर्शन का मुख्य आधार नीट पेपर लीक,छात्रों के साथ कथित पुलिस कार्रवाई तथा शिक्षा संबंधी मुद्दे बताए गए।विपक्ष का कहना था कि वह छात्रों की आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहता है, जबकि सत्तापक्ष ने इसे सुरक्षा व्यवस्था और संवैधानिक मर्यादाओं के विरुद्ध राजनीतिक प्रदर्शन बताया। पीएम आवास जैसे अति- संवेदनशील और उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन ने स्वाभाविक रूप से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाई और राजनीतिक वातावरण और अधिक गर्म हो गया।इसके तुरंत बाद प्रमुख सत्ताधारी पार्टी ने भी प्रमुख विपक्षी पार्टी के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन प्रारंभ कर दिए।अनेक राज्यों में प्रमुख सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और विपक्ष के आरोपों का प्रतिवाद किया।यह घटनाक्रम लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा का स्वाभाविक हिस्सा माना जा सकता है, किंतु जब जवाबी प्रदर्शन भी समान तीव्रता से शुरू होते हैं तो राजनीतिक तनाव कई गुना बढ़ जाता है। तेलंगाना सहित कुछ स्थानों पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पों की मीडिया में आई खबरों ने चिंता और बढ़ा दी। लोकतंत्र में विचारों का संघर्ष स्वीकार्य है,परंतु यदि वह शारीरिक टकराव का रूप लेने लगे तो लोकतांत्रिक संस्कृति कमजोर पड़ने लगती है। साथियों,आज सूचना प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया के युग में भारत की प्रत्येक राजनीतिक गतिविधि केवल देश की जनता ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व भी देखता है। भारत स्वयं को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में प्रस्तुत करता है। ऐसे में संसद के भीतर लगातार व्यवधान, सड़क पर राजनीतिक संघर्ष, आरोप-प्रत्यारोप और कार्यकर्ताओं के बीच टकराव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लोकतांत्रिक परिपक्वता के संदर्भ में चर्चा का विषय बनते हैं। लोकतंत्र की शक्ति केवल चुनावों में नहीं, बल्कि असहमति को गरिमा के साथ संभालने की क्षमता में भी निहित होती है। साथियों,राजनीतिकविश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि जनता अब केवल भाषणों और नारों के आधार पर निर्णय नहीं करती।मतदाता शिक्षा, रोजगार, महंगाई,कृषि स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, कानून-व्यवस्था और आर्थिक अवसरों जैसे ठोस मुद्दों पर सरकार और विपक्ष दोनों का मूल्यांकन करता है। यदि संसद का समय बार-बार हंगामे में व्यतीत होता है और जनहित के प्रश्न पीछे छूट जाते हैं, तो मतदाता दोनों पक्षों के आचरण का आकलन अपने अनुभव और अपेक्षाओं के आधार पर करता है।इसलिए कई विश्लेषक यह संभावना व्यक्त करते हैं कि अंततः जनता अपने मताधिकार के माध्यम से राजनीतिक दलों के व्यवहार पर प्रतिक्रिया देती है। यह प्रतिक्रिया किसके पक्ष में जाएगी, इसका निर्णय केवल चुनाव परिणाम ही करते हैं; इसलिए, किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। साथियों,लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। एक सशक्त विपक्ष सरकार को जवाबदेह बनाता है, नीतियों की समीक्षा करता है और वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। दूसरी ओर सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वह आलोचना को लोकतांत्रिक भावना से सुने, संवाद के अवसर बनाए और आवश्यक होने पर सुधारात्मक कदम उठाए। यदि दोनों पक्ष संवाद छोड़कर केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण को प्राथमिकता देंगे, तो लोकतंत्र की गुणवत्ता प्रभावित होगी।जनता पर इन घटनाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव भी कम नहीं पड़ता। संसद का कामकाज बाधित होने से अनेक विधेयकों, नीतिगत चर्चाओं और जनहित से जुड़े निर्णयों में विलंब हो सकता है। दूसरी ओर,संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर धरना- प्रदर्शन होने से आम नागरिकों को यातायात, सुरक्षा जांच और दैनिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करनापड़ता है। तीसरा प्रभाव लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विश्वास पर पड़ता है। यदि नागरिकों को यह महसूस होने लगे कि समस्याओं का समाधान संसद के बजाय केवल सड़क पर संघर्ष से ही संभव है, तो संस्थागत लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग सकता है। भारतीय संविधान ने नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा का अधिकार दिया है।

साथ ही यह भी अपेक्षा की गई है कि इन अधिकारों का प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और संवैधानिक मर्यादाओं के अनुरूप हो। इसी प्रकार निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा रहती है कि वे संसद और विधानसभाओं को संवाद, बहस और नीति- निर्माण का सर्वोच्च मंच बनाए रखें।

यह हमारे ही बच्चे हैं, अपना ही यूथ है

महात्मा गांधी जिन्होंने अनशन को प्रसिद्ध किया था, ने इसके बारे बताया था कि यह कोई सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, यह आध्यात्मिक और नैतिक अहिंसक हथियार है। उनका प्रयास अन्याय को पराजित करने के लिए विरोधी की अंतरात्मा को जगाना है। आजादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी जी ने17-18 बड़े उपवास रखे थे और कई कम अवधि के उपवास थे। उनका सबसे प्रसिद्ध अनशन आजादी के बाद कोलकाता में था। हिन्दू-मुसलमान दंगों को रोकने के लिए उन्होंने 1 सितम्बर 1947 को वहां अपना अनशन शुरू कर दिया था। अगले ही दिन से दोनों तरफ के दंगाइयों ने उनके पैरों पर अपने-अपने हथियार रखने शुरू कर दिए। तीसरे दिन महात्मा गांधी जी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया था। इस पर लार्ड माउंटबेटन ने कहा था, जो काम (दंगे रोकना) पंजाब में मेरे50000 सैनिक नहीं कर सके,वह एक निहत्थे व्यक्ति ने कर दिखाया। इस देश ने सदैव उन लोगों की इज्जत की है जो निःस्वार्थ दूसरों के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार है। जयप्रकाश नारायण ने भी गांधी जी की तरह अच्छा आंदोलन चलाया था। 59 वर्षीय सोनम वांगचुक न गांधी हैं और न ही जयप्रकाश नारायण,पर बड़ी देर के बाद उन्होंने देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया है, क्योंकि वह भी दूसरों के लिए कष्ट सह रहे हैं। उनका मजाक में कहना था कि 'अगर मैं मर गया तो भूत बन कर वापिस आऊंगा! हम नहीं चाहते कि सोनम वांगचुक भूत बन कर लौटें। उन जैसे लोगों की देश को बहुत जरूरत है। सोनम वांगचुक, उनका अनशन, जन्तर-मंतर पर प्रदर्शन, संसद की तरफ मार्च और युवाओं पर बर्बर लाठीचार्ज देश और विदेश में चर्चा का विषय बन चुका है। लंदन में भी भारतीय छात्र प्रदर्शन कर चुके हैं। बेहतर होता कि धर्मेन्द्र प्रधान खुद लाल बहादुर शास्त्री की तरह इस्तीफा दे देते । सी-वोटर सर्वेक्षण के अनुसार 66% देशवासी चाहते हैं कि धर्मेन्द्र प्रधान को नीट पेपर लीक और सीबीएसई विवाद के कारण इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे एकदम तो शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होगी, पर यह संदेश तो जाएगा कि नेतृत्व लोगों की शिकायतों के प्रति संवेदनशील है। नीट पेपर लीक के बाद12 से अधिक युवा आत्महत्या कर चुके हैं। धर्मेन्द्र प्रधान को हटाने के लिए सरकार को मजबूर नहीं किया जा सकता लेकिन युवाओं का संघर्ष उनकी समस्याओं को सैंटर स्टेज पर लाने में सफल रहा है। सोनम वांगचुक का योगदान बहुत है। गांधी जी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने वांगचुक के बारे सही कहा है कि लम्बे समय के बाद उन्होंने समाज की चेतना को जगाया है। उनकी इस गांधीवादी क्रिया में एक और सुखद संदेश भी छिपा है कि हम सब कुछ खो नहीं बैठे। रोज दलबदल करते नेताओं से अलग देश में अभी भी सोनम वांगचुक जैसे लोग मौजूद हैं जो दूसरों के लिए जान देने को तैयार है। अनुमान है कि देश की जनसंख्या का 22प्रतिशत , 18-29 आयु के बीच है। इस युथ में बहुत हताशा है। पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन तो मात्र लक्षण है, समस्या बहुत गहरी है। हमारी शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। पर हमारा सारा ध्यान सांसदों को तोड़ने पर लगा हुआ है। लोग देख रहे है कि वह किसी एक पार्टी के लिए वोट देते हैं, पर लालच या दबाव में उनके प्रतिनिधि विपक्ष से जाकर मिल जाते है। इससे राजनीति के प्रति निराशावाद बढ़ रहा है। ऐसा प्रभाव मिलता है कि जैसे राजनीति देश को एक तरफ छोड़ कर अपनी ही अलग दिशा में भटक रही है। चुनावी राजनीति पर तो प्रश्न चिन्ह लग रहा है। हम पांचवीं या छठी अर्थव्यवस्था हैं, पर हमारा विकास बराबर नौकरियां पैदा नहीं कर रहा। हम जॉब-लैस ग्रोथ देख रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय में हम नम्बर 140 पर है। यही भी कारण है कि इतने पढ़े-लिखे युवा जंतर-मंतर पर इकट्ठा हैं। अफसोस की बात है कि यह सरकार सीधे संवाद करने में विश्वास नहीं रखती। एक तरफा संवाद होता है। किसान आंदोलन के दौरान भी राजहठ देखने को मिला था। परिणाम हुआ कि आखिर में कानून वापिस लेने पड़े। इसी तरह जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, से संवाद नहीं किया जा रहा। केवल मंत्री जेपी नड्डा से 10 मिनट की बातचीत हुई है। 1984 में लद्दाख की मांगों को लेकर सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांगयाल अनशन पर बैठ गए थे। अनशन के 16वें दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद दिल्ली से लेह गईं और उन्हें अनशन तोड़ने के लिए मनाने में सफल रहीं। उन्हें जूस पिलाया और स्थिति को सम्भाल लिया। यह नेतृत्व होता है जो हर बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाता। अपने ही लोगों से संवाद करने से इज्जत कम नहीं होती। मुझे विश्वास है कि अगर अब भी सरकार आंदोलनकारियों से बात करे तो स्थिति को शांत किया जा सकता है। जो अप्रिय दृश्य हम संसद के नजदीक देख कर हटे हैं, वह न देखने पड़ते। सरकारी संवेदनशीलता दिखाने की बहुत जरूरत है। हमारे देश में जो सरकार का विरोध करता है उसे बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। उसके खिलाफ मीडिया या सोशल मीडिया से अभियान चलाया जाता है। एंटी नेशनल करार दिया जाता है। जिस प्रकार जंतर-मंतर पर युवाओं ने जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, को आईना दिखाया है उससे उनकी भी आंखें खुल जानी चाहिए। उन्हें भी अब सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है। यह भी समझ लेना चाहिए कि सोशल मीडिया के युग में कुछ नहीं छिपाया जा सकता। पर मैं राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के प्रधानमंत्री निवास के बाहर हाई सिक्योरिटी जोन पर धरना देने से सहमत नहीं हूं। पहले कांग्रेस का कॉकरोच जनता पार्टी के प्रति रवैया उदासीन था। उसे आप का अभियान समझा गया। लाठीचार्ज के बाद वह तेज हो गए जो जिनकी काम भी है, पर प्रधानमंत्री निवास के बाहर धरना अनुचित था। एकदम जो फोकस दिल्ली में सोमवार की घटनाओं पर था वह राहुल गांधी पर चला गया। सरकार को राहुल गांधी का धन्यवाद करना चाहिए। संसद भवन के आसपास सोमवार के जो विजुअल देखने को मिल रहे है उनसे दिल दहल जाता है। युवाओं पर बुरी तरह से लाठीचार्ज किया गया। पीछे भाग-भाग कर पीटा गया। एक लड़की आईसीयू में है। अस्पतालों में दर्जनों युवा भर्ती किए गए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट ने यह बताया है, पुलिस से बचने के प्रयास में जब प्रदर्शनकारी दहशत में भाग रहे थे तो कई जमीन पर गिर गए। महिलाएं रो रही थीं। सोशल मीडिया ऐसे वीडियो से भरा हुआ है जहां पुलिस प्रदर्शनकारियों जिनमें महिलाएं भी थीं, को पीट रही थी और कई जमीन पर बेहोश पड़े थे। प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी पथराव किया गया है, पर इस लाठीचार्ज के बाद मामला और भड़क गया है। मामला पेपर लीक से आगे बढ़ गया है। अब तो यह मायने नहीं रखता कि किसने आंदोलन शुरू किया था या अब कौन नेतृत्व कर रहा है। कोई कर भी रहा या नहीं? मायने यह रखता है कि देश की राजधानी में देश का युवा अपनी बात कहने आया था, पर बात सुनने की जगह उस पर लाठी बरसाई गई। एक लोकतांत्रिक सरकार के शासन में ऐसा नहीं होना चाहिए। यह युवा जायज सवाल खड़े कर रहे है। अगर आप समझते है कि वह गलत है तो प्यार से समझाइए, लाठी से नहीं। लेकिन जंतर-मंतर से जो युवा इकट्ठे हुए है, को देख कर आशा भी होती है। आशा इस बात से कि हमारे पास कितने प्रतिभाशाली युवा है।

अभिनीत दीपके जो खुद अनशन पर बैठ गए है, बॉस्टन में पढ़ रहे हैं। तीन युवा जो भी अनशन पर बैठे है, नेहा, अभिलेन और मनोष कुमार, तीनों पीएचडी स्कालर है। जंतर-मंतर पर ऐसे प्रतिभाशाली युवा भरे पड़े हैं। सब देश की हालत और अपने भविष्य को लेकर चिन्तित है। इस देश में तो सरकारी चपरासी की नौकरी के लिए एमबीए तक लाइन में लग जाते है। इसीलिए चिन्ता भी होती है कि इनका बनेगा क्या? इनके लिए अच्छी नौकरी कहां से आएगी? शिक्षा महंगी हो रही है। हर साल कोटा से आत्महत्या की दर्दनाक खबरें मिलती हैं। क्या इस पर संसद में राजनीति से ऊपर उठ कर सार्थक चर्चा होगी? क्या सरकार इस पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएगी ताकि समाधान निकल सके और युवाओं को आभास हो कि कोई उनको भी सुन रहा है? जब तक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार नहीं होता देश सही प्रगति नहीं करेगा। शिक्षा पर हमारा निवेश दूसरे विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है।

अमेरिका अपनी जीडीपी का 5.43फीसदी शिक्षा पर खर्च करता है जब कि हम केवल 4.12% ही खर्च करते हैं। क्या युवाओं की आवाज सुनी जाएगी या यह उनकी पुकार अनसुनी कर दी जाएगी? हर बात वोटिंग और नम्बरों की नहीं होती। देखना यह है कि इससे आप बनाते क्या हो?जो आंदोलन शांतिमय था उस पर लाठीचार्ज किया गया,पत्थर बरसाए गए।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भारती ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, [illegible] एक्स. दिल्ली-31, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भारती, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DEL/HIN/2014/…)

जैव ऊर्जा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में एफपीओ की भूमिका होगी मजबूत, किसानों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर

कुशीनगर।

उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन एवं किसानों को पराली प्रबंधन से जोड़कर अतिरिक्त आय के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में एफपीओ को बायोमास (पराली) की प्रत्यक्ष आपूर्ति का अधिकार देने, इंडियन ऑयल के साथ सीधे अनुबंध की व्यवस्था, बैंक द्वारा सब्सिडी समायोजन, कैश क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने तथा बिचौलियों की व्यवस्था समाप्त करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि जैव ऊर्जा नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए किसानों, एफपीओ, इंडियन ऑयल और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। उन्होंने उप निदेशक कृषि को निर्देश दिए कि एफपीओ, वेंडरों एवं विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक किसानों की सहभागिता सुनिश्चित कराई जाए, ताकि सीएनजी प्लांट के लिए पर्याप्त मात्रा में पराली उपलब्ध हो सके।

उन्होंने कहा कि पराली का वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक उपयोग पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने और जैव ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा देगा। बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं एफपीओ प्रतिनिधियों से इस दिशा में सक्रिय सहयोग करने का आह्वान किया गया। बैठक में उप निदेशक कृषि, जिला कृषि अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक तथा कृषि विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

कस्तूरबा विद्यालयों में खत्म होगा बिजली संकट, लगेंगे सोलर प्लांट

सौर ऊर्जा संयंत्रों से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में छात्राओं की पढ़ाई होगी निर्बाध

देवरिया। जनपद में दूर-दराज के ग्रामीण अंचलों में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) को मूलभूत सुविधाओं से लैस करने और बालिकाओं की पढ़ाई में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कलेक्ट्रेट प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। बिजली की अनिश्चित कटौती से पठन-पाठन और आवासीय व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए जिले के सभी कस्तूरबा विद्यालयों को सौर ऊर्जा से संतृप्त करने की कार्ययोजना पर काम शुरू हो गया है। गुरुवार को जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में सभी कस्तूरबा विद्यालयों की प्रधानाचार्यों के साथ जूम ऐप के माध्यम से एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने सभी विद्यालयों की प्रधानाचार्यों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे अपने-अपने संस्थानों में आवश्यकतानुसार सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए तत्काल तकनीकी आंकलन कर विस्तृत प्रस्ताव तैयार करें। इन प्रस्तावों को स्वीकृति हेतु शासन तथा उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (नेडा) को प्राथमिकता के आधार पर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक मंशा यह है कि सुविधाओं और बिजली के अभाव में बालिकाओं की शिक्षा और आवासीय दिनचर्या पर प्रतिकूल असर न पड़े। ?अधिकारियों ने अवगत कराया कि कस्तूरबा विद्यालयों में अक्सर रात के समय या भीषण गर्मी में विद्युत आपूर्ति बाधित होने से छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सोलर प्लांट की स्थापना के बाद इन आवासीय परिसरों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी, जिससे पंखे, लाइट और पानी के पंप बिना रुकावट चलेंगे। मुख्य विकास अधिकारी ने प्रधानाचार्यों को हिदायत दी कि विभागीय औपचारिकताएं अविलंब पूरी कर प्रस्ताव शासन को भेजें, ताकि समयबद्ध तरीके से संयंत्रों की स्थापना कराई जा सके।

ट्रेनों में चोरी करने वाला शातिर दबोचा, जीआरपी ने 8 घंटे में सुलझाई वारदात

देवरिया।

सोने का लॉकेट और नकदी समेत 41 हजार से अधिक का सामान बरामद

पूर्वोत्तर रेलवे के यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों में आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत जीआरपी थाना देवरिया को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए मात्र आठ घंटे के भीतर रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक अंतरमंडलीय शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी के पास से चोरी का सोने का लॉकेट और नकदी बरामद कर कई थानों से जुड़े आपराधिक मामलों का पटाक्षेप किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक रेलवे बलिया सवि रत्न गौतम के निकट पर्यवेक्षण में चलाई जा रही चेकिंग के दौरान जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने देवरिया सदर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर दो से संदिग्ध हालत में घूम रहे पंकज मिश्रा को हिरासत में लिया।

रुद्रपुर थाना क्षेत्र के बौरहीह निवासी 36 वर्षीय आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास से एक पीली धातु (सोना) का लॉकेट और 6,900 रुपये नकद बरामद हुए, जिसकी कुल कीमत लगभग 41,900 रुपये आंकी गई है। बरामद रकम और आभूषण का मिलान करने पर बड़ा खुलासा हुआ। बरामद नकदी में से 2,000 रुपये जीआरपी थाना बलिया और 4,900 रुपये जीआरपी थाना मऊ में दर्ज मामलों से संबंधित पाए गए, जबकि सोने का लॉकेट देवरिया जीआरपी थाने में हाल ही में दर्ज मुकदमे से जुड़ा निकला। आरोपी ट्रेनों व प्लेटफॉर्मों पर सो रहे यात्रियों के कीमती सामान पर हाथ साफ करता था और उसे औने-पौने दामों में बेचकर अपने शौक पूरे करता था। वह देवरिया स्टेशन पर चोरी का लॉकेट बेचने की फिराक में आया था, तभी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस सफल कार्रवाई में जीआरपी के उपनिरीक्षक राजीव सिंह, आरपीएफ एएसआई संजय कुमार मिश्रा, मुख्य आरक्षी रजनीश यादव, धीरेंद्र चौहान, आरक्षी प्रमोद यादव और दीनानाथ की सराहनीय भूमिका रही।

30 जुलाई तक साथी पोर्टल पर पंजीकरण कराएं बीज विक्रेता, नहीं तो लाइसेंस होगा निरस्त

कुशीनगर। जनपद के सभी पंजीकृत बीज विक्रेताओं के लिए भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित 'साथी पोर्टल' पर 30 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। निर्धारित समय-सीमा तक पंजीकरण नहीं कराने वाले विक्रेताओं का बीज विक्रय प्राधिकार-पत्र (लाइसेंस) निरस्त कर दिया जाएगा। जिला कृषि अधिकारी एस.के. सिंह ने बताया कि साथी पोर्टल के माध्यम से बीज के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण एवं बिक्री की पूरी व्यवस्था को डिजिटल, पारदर्शी और ट्रेसेबल बनाया जाएगा, जिससे बीज की गुणवत्ता एवं प्रमाणिकता का प्रभावी सत्यापन संभव होगा। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया और ऑनलाइन लिंक सभी थोक बीज विक्रेताओं को उपलब्ध करा दिए गए हैं। साथ ही प्रत्येक फुटकर एवं पंजीकृत बीज विक्रेता का लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी संबंधित थोक विक्रेता को भेज दिया गया है। जिला कृषि अधिकारी ने सभी बीज विक्रेताओं से अपने संबंधित थोक विक्रेता से संपर्क कर ऑनलाइन लिंक प्राप्त करने तथा बीज अनुज्ञापन पत्र (लाइसेंस), पैन कार्ड, आधार, जीएसटी एवं प्रतिष्ठान से संबंधित आवश्यक अभिलेख अपलोड कर 30 जुलाई, 2026 तक पंजीकरण पूरा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पंजीकरण के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर संबंधित विक्रेता जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में स्थित बीज पटल सहायक से संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

मातृ-शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाने को प्रशासन मुस्तैद, कलेक्ट्रेट में सीएचओ को मिला प्रशिक्षण

सीएमओ ने प्रत्येक मातृ-शिशु मृत्यु का ऑडिट करने के दिए निर्देश

देवरिया। जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं को धरातल पर पारदर्शी व असरदार बनाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक चिकित्सीय सुविधाओं की पहुंच सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट प्रशासन ने अहम कदम उठाया है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने सीएचओ को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य योजनाओं की सबसे मजबूत कड़ी करार देते हुए अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के निर्देश दिए। प्रशिक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने वीएचएनडी सत्रों के प्रभावी अनुश्रवण पर बल देते हुए कहा कि क्षेत्र में तैनात आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। उन्होंने ताकीद की कि गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच, प्रसव पूर्व देखभाल और बच्चों के नियमित टीकाकरण में किसी तरह की लापरवाही न हो। सत्रों के दौरान आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य तंत्र का प्राथमिक लक्ष्य जनपद में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाना है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. ए.के. गुप्ता ने कहा कि प्रशिक्षण में दी गई तकनीकी जानकारियों का धरातल पर अक्षरशः अनुपालन होना चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में होने वाली प्रत्येक मातृ और शिशु मृत्यु का अनिवार्य रूप से ऑडिट किया जाए, ताकि कारणों का सटीक विश्लेषण कर व्यवस्थागत कमियों को समय रहते दूर किया जा सके। डॉ. अंकिता के समन्वय में आयोजित इस सत्र में टीएसयू के सतीश सिंह सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रशिक्षकों ने सीएचओ को उनके प्रशासनिक व चिकित्सकीय दायित्वों की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी के निर्देशों पर भारतीय खाद्य निगम के एस0डब्ल्यू0सी0 किर्तापुर डिपो का निरीक्षण

जौनपुर।

जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) परमानन्द झा द्वारा भारतीय खाद्य निगम के एस0डब्ल्यू0सी0 किर्तापुर डिपो का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि रबी विपणन वर्ष 2026-27 के अन्तर्गत समस्त क्रय संस्थाओं द्वारा कुल गेहूँ खरीद 32216.016 मी0टन के सापेक्ष क्रय केन्द्रों से कुल 29047.94 मी0टन गेहूँ भारतीय खाद्य निगम में सम्प्रदान हेतु प्रेषित किया जा चुका है, 3168.08 मी0टन गेहूँ का प्रेषण किया जाना शेष है, जिसमें पी0सी0एफ0 संस्था का 1105.877 मी0टन, खाद्य विभाग का 1054.77 मी0टन, पी0सी0यू0 संस्था का 947.489 मी0टन व नैफेड संस्था का 58.45 मी0टन अधिक मात्रा में शेष है। निरीक्षण के समय मौके पर गेहूँ के 03 ट्रक उतार हेतु खड़े पाये गये तथा डिपो पर 01 प्वाइंट लेबर (कुल 12 श्रमिक) उपलब्ध पाये गये। जिस पर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) द्वारा उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करते हुये समस्त क्रय संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर अवशेष शत-प्रतिशत गेहूँ का सम्प्रदान प्रत्येक दशा में 31 जुलाई 2026 से पूर्व कराये जाने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटन माह अगस्त, 2026 के नेट खाद्यान्न आवंटन 17627.05 मी0टन के सापेक्ष अद्यतन 9215.10 मी0टन (52.28 प्रतिशत) खाद्यान्न का उठान विभिन्न गोदामों से होना पाया गया। किर्तापुर गोदाम से प्राप्त रिलीज आर्डर 1493 मी0टन के सापेक्ष 1492.548 मी0टन खाद्यान्न का उठान हो चुका है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में आयुक्त महोदय, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा आगामी मानसून/वर्षा ऋतु से उत्पन्न होने वाली रसद एवं भण्डारण सम्बन्धी चुनौतियों के दृष्टिगत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाभार्थियों को खाद्यान्न की आपूर्ति समय से सुनिश्चित कराने हेतु माह अक्टूबर, 2026 तक आवंटित खाद्यान्न का अग्रिम उठान 31 अगस्त, 2026 तक पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये है। किन्तु जनपद के भण्डारण गोदामों-जासोपुर गोदाम एवं शिवांगनी वेयर हाउस में खाद्यान्न के उठान/उतार हेतु प्रायः पर्याप्त संख्या में श्रमिक उपलब्ध नहीं हो पाते है, जिसके कारण खाद्यान्न उठान/गेहूँ के उतार की गति धीमी है। जिस पर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये डिपो प्रबन्धक भारतीय खाद्य निगम तथा प्रबन्धक राज्य भण्डारण निगम (एस0डब्ल्यू0सी0) किर्तापुर को सम्बन्धित ठेकेदार के माध्यम से समस्त गोदामों पर आवश्यक संख्या में श्रमिकों की प्रतिदिन उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा भारत सरकार को मंशानुरूप निर्धारित अवधि में खाद्यान्न उठान कराये जाने के कड़े निर्देश दिये गये। निरीक्षण के अवसर पर डिपो पर जिला खाद्य विपणन अधिकारी, डिपो प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, किर्तापुर, प्रबन्धक, एस0डब्ल्यू0सी0 किर्तापुर व क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, सदर/प्रेषण प्रभारी, किर्तापुर उपस्थित रहे।

जिला सलाहकार समिति की बैठक में युवा सहभागिता बढ़ाने पर जोर

कुशीनगर। जिला प्रशासन एवं मेरा युवा भारत, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर एवं मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने की। जिला युवा अधिकारी चन्द्रभूषण चौबे ने बताया कि बैठक में जनपद में युवाओं की सहभागिता बढ़ाने तथा MY Bharat के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। MY Bharat पोर्टल पर अधिकाधिक युवाओं का पंजीकरण कराने के लिए व्यापक अभियान चलाने तथा विभिन्न विभागों और शैक्षणिक संस्थानों के समन्वय से इसे गति देने पर बल दिया गया। बैठक में MY Bharat की उपलब्धियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। साथ ही नशा मुक्ति अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप देने के लिए युवाओं, स्वयंसेवी संगठनों और शिक्षण संस्थानों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर विचार-विमर्श हुआ। इसके अलावा स्वयंसेवी गतिविधियों, नेतृत्व विकास, सामुदायिक सेवा और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विभिन्न युवा-केंद्रित कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्यक्रमों का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

'छात्र सड़क पर हैं तो हम भी उनके साथ': राहुल गांधी की बस यात्रा से गरमाई सियासत, गांधी स्मृति पहुंचा विपक्ष

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में नीट-यूजी पेपर लीक को लेकर सियासी तापमान और बढ़ गया है। गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के सांसद एकजुट होकर गांधी स्मृति पहुंचे।

राहुल गांधी अपने सरकारी आवास से विपक्षी नेताओं के साथ एक बस में सवार होकर निकले। इस दौरान कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई(एम) समेत कई विपक्षी दलों के सांसद उनके साथ मौजूद रहे। हालांकि, यात्रा शुरू होने से पहले कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई। राहुल गांधी के आवास के बाहर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी और बस को आगे बढ़ने से रोक दिया। कुछ मिनट तक चली बातचीत के बाद पुलिस ने रास्ता खोल दिया, जिसके बाद विपक्षी नेताओं का काफिला गांधी स्मृति के लिए रवाना हो गया।

'छात्र सड़क पर हैं, इसलिए हम भी सड़क पर हैं'

रवाना होने से पहले राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्र अपने भविष्य को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में विपक्ष का कर्तव्य है कि वह उनके साथ खड़ा रहे। उन्होंने कहा, 'हम पहले इंडिया गेट जाना चाहते थे, लेकिन हमें अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद हमने गांधी स्मृति जाने का फैसला किया, वहां भी हमें कुछ देर रोका गया। हमारा सबसे बड़ा संदेश देश के छात्रों के लिए है कि हम आपके साथ हैं और आपकी आवाज संसद से लेकर सड़क तक उठाएंगे।'

पहले हुई रणनीति बैठक, फिर निकला विपक्ष का काफिला

गांधी स्मृति मार्च से पहले राहुल गांधी ने अपने आवास पर विपक्षी सांसदों की बैठक बुलाई थी। बैठक में नीट पेपर लीक, संसद में सरकार को घेरने की रणनीति और छात्रों के समर्थन में संयुक्त कार्यक्रम पर चर्चा हुई। इसके बाद सभी नेताओं ने एक साथ बस से गांधी स्मृति जाने का फैसला किया। बैठक की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी। इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ भी आवास के बाहर जुटने लगी।

विपक्ष ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

आरजेडी सांसद संजय यादव ने कहा कि पिछले दस वर्षों में देशभर में 152 पेपर लीक हुए, लेकिन आज तक किसी बड़े आरोपी को सजा नहीं मिली। उनके मुताबिक शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता खत्म हो चुकी है और लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। वहीं, सीपीआई(एम) सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि विपक्ष गांधी स्मृति इसलिए जा रहा है क्योंकि सरकार छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा छात्रों के साथ एकजुटता और लोकतांत्रिक विरोध का प्रतीक है।

सिब्बल बोले- सरकार पहले अपने नेताओं पर फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए

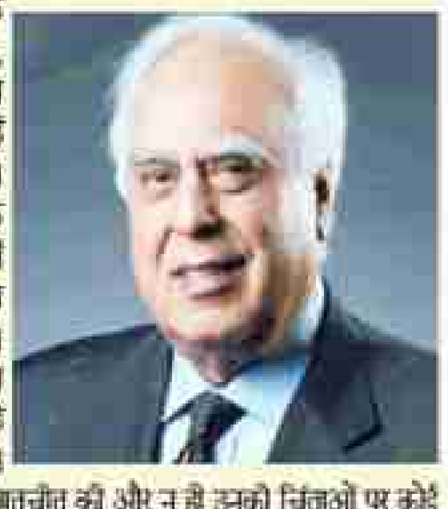

नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार पहले अपनी पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए, जिन पर पहले गंभीर आरोप लगाए गए थे और बाद में उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया गया। उन्होंने सवाल किया कि उनके खिलाफ सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही और पहले से चल रही जांच क्यों रोक दी गई। सिब्बल ने कहा कि छात्रों का आंदोलन 28 जून से चल रहा है और 25 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान सरकार ने न तो छात्रों से बातचीत की और न ही उनकी चिंताओं पर कोई बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब छात्र भूख हड़ताल पर बैठे थे, तब सरकार चुप रही और अब युवाओं के बढ़ते गुस्से को देखकर सरकार सक्रिय हुई है।

विपक्ष की प्रमुख मांगें

नीट विवाद को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बना रहा है। विपक्ष की प्रमुख मांगें हैं-

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें।

नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच हो।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की जवाबदेही तय की जाए।

दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

'पेपर लीक पर आएगा नया कानून' प्रधानमंत्री मोदी का छात्रों को संदेश

कहा- आज कैबिनेट बैठक में होंगे और सख्त फैसले

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात नीट पेपर लीक के मुद्दे पर एक बार फिर से आंदोलन कर रहे छात्रों के लिए संदेश जारी किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में पेपर लीक होने के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी ने वीडियो संदेश में कहा, ''मैं जानता हूं कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले छह महीनों में अनेक वैध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है। वह जेल में पड़े हैं।'' प्रधानमंत्री ने आगे कहा, ''हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा हो जाए। इसका प्रबंध किया जाए। और अभी पांच-छह दिन पहले रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं।'' उन्होंने आगे कहा, ''लेकिन, हम वहां संतोष मानने वालों में से नहीं हैं। इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए।

फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, नड्डा-जितेंद्र सिंह की वांगचुक से मुलाकात

आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मसौदा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के मसौदा पर आज कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।'' इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार की सुबह को पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

पुलिस बर्बरता के खिलाफ सीजेपी करेगी आज राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन

नई दिल्ली।

सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह कॉकरोच जनता पार्टी के साथ किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा- सरकार बुधवार दोपहर से गुरुवार दोपहर तक उनके प्रतिनिधियों को चार बार बातचीत का ऑफर दे चुकी है। जितेंद्र सिंह ने कहा- जेपी नड्डा के ऑफिस या उनके आवास, किसी भी जगह बातचीत हो सकती है। हम दोनों वहां मौजूद रहेंगे। हम इसे प्रतिष्ठा का विषय नहीं मानते। मैं अपील करता हूं कि आइए और बातचीत कीजिए। बातचीत के जरिए धीरे-धीरे हम समाधान की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी तरफ सीजेपी ने कहा है कि सरकार को बातचीत करनी है तो जंतर-मंतर आए या किसी न्यूट्रल जगह पर बातचीत करें। सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने कहा- हमें पुलिस ने बताया कि सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया है। लेकिन हम किसी के घर या ऑफिस नहीं जाएंगे। दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशन लगातार दूसरे दिन बंद रहे। बाद में झंडेवाला मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया।

स्टेशनों के बंद रहने से सैकड़ों ऑफिस जाने वाले लोगों और अन्य यात्रियों को लंबा और महंगा रास्ता अपनाना पड़ा। एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया। स्टाग्राम पर उन्होंने लिखा- छात्रों का संकल्प हम सभी से सवाल करता है कि क्या हम सच में उन युवाओं की बात सुन रहे हैं, जो इस देश का भविष्य हैं। भविष्य उन्हीं का है।

26 दिनों से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कहा- बच्चों को अपराधी की तरह पेश नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेताओं को प्रधानमंत्री आवास के बजाय जंतर-मंतर जाकर छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए था।

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। एक जनहित याचिका में अपील की गई है कि प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली को बंधक बना दिया है। कई सड़कें बंद हैं और आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

- जितेंद्र सिंह बोले- सरकार किसी भी समय, हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार
- पीएम मोदी के ऐलान पर अभिजीत दिपके का रिप्लाई, कहा- धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए
- सीजेपी ने कहा- नड्डा के घर-ऑफिस नहीं जाएंगे, बात करनी है तो सरकार जंतर-मंतर आए

डीयू ने छात्रों और शिक्षकों के लिए जारी की एडवाइजरी, प्रदर्शनों से दूर रहने के लिए कहा

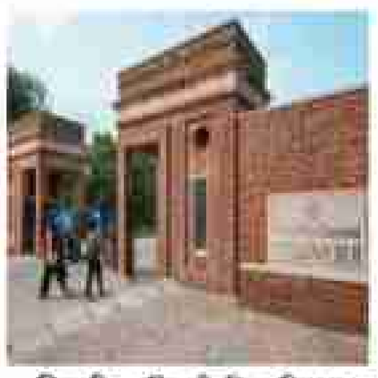

दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने छात्रों और शिक्षकों को जंतर-मंतर पर प्रदर्शनों से दूर रहने की सलाह दी गई है। विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, ऐसे प्रदर्शनों पर सख्त नियम लागू हैं। प्रदर्शनों में शामिल होने से कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वहीं, दिल्ली ने एक्स पर कहा, पुलिस का आज रात चल रहे विरोध-प्रदर्शन पर कोई कार्रवाई करने का प्लान नहीं है। लोगों को सलाह दी है कि कोई भी गुमराह करने वाली या बिना पुष्टि वाली जानकारी न फैलाएं। डीयू ने कहा, प्रदर्शन के दौरान की गतिविधियों से छात्रों की व्यक्तिगत सुरक्षा को गंभीर खतरा है। यह उनकी शैक्षणिक प्रगति को भी प्रभावित कर सकता है। साथ ही, पेशेवर अवसरों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। सभी छात्रों से अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया है। उन्हें कानून का पालन करने की भी सलाह दी गई है। छात्रों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। स्थिति को भड़काने के लिए फर्जी और भ्रामक सामग्री फैलाई जा रही है।

छात्रों के समर्थन में मौन हुए अन्ना पीएम मोदी को चिट्ठी लिख जताया दुख

अहिल्यानगर। दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को अब वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे का भी समर्थन मिल गया है। बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में अन्ना हजारे ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने करीब दो घंटे तक मौन आंदोलन किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर चिंता जताई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पूरे मामले में हस्तक्षेप की अपील की।

दो घंटे का मौन आंदोलन, सरकार तक पहुंचाया संदेश

अन्ना हजारे का मौन प्रदर्शन सुबह 11 बजे शुरू हुआ और दोपहर एक बजे समाप्त हुआ। उन्होंने बिना भाषण दिए शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। आंदोलन खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि देश के सर्वोच्च नेतृत्व तक जनता और छात्रों की पीड़ा पहुंचाना उनका कर्तव्य है। इसके बाद वह अपने गांव रालेगण सिद्धि लौट गए। अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे पत्र में दिल्ली में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को दुखद बताया। उन्होंने लिखा कि युवाओं का आक्रोश केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि उनके भविष्य और व्यवस्था पर भरोसे से जुड़ा सवाल है। उनके मुताबिक सरकार को इस मामले को संवेदनशीलता के साथ देखने की जरूरत है। अन्ना हजारे ने आगे यह भी कहा कि यदि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तो इससे सरकार कमजोर नहीं होगी। इसके उलट सरकार की जवाबदेही तय होगी और जनता का भरोसा बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जवाबदेही ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अन्ना हजारे ने यह भी कहा है कि छात्रों के गुस्से का जवाब लाठीचार्ज नहीं हो सकता। उन्होंने सरकार से अपील की कि बल प्रयोग के बजाय छात्रों से सीधे बातचीत कर समाधान निकाला जाए। उनका मानना है कि संवाद से ही विवाद खत्म हो सकता है।

'सरकार चर्चा चाहती तो पहले दिन ही कर लेती'; नीट विवाद पर खरगे ने केंद्र पर उठाए सवाल

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के आरोप का खंडन किया कि विपक्ष परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक पर चर्चा से भाग रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार असल में बहस चाहती, तो उसने विपक्ष की पहली मांग पर ही इसकी अनुमति दे दी होती। पत्रकारों से बात करते हुए, खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इस मुद्दे पर उनके इरादों पर सवाल उठाया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। खरगे ने कहा 'अगर वे चर्चा के लिए तैयार होते, तो जिस दिन हमने इसकी मांग की थी, उसी दिन से शुरू हो जाती। वे तैयार क्यों नहीं थे? बाद में, अपने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। हम सांसद हैं, लेकिन सत्ताधारी दल के लोगों ने खुद आज दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। जब तक वे (धर्मेंद्र प्रधान) इस्तीफा नहीं देते, तब तक यह काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री अब तक चुप क्यों हैं? अगर इस स्थिति के लिए कोई जिम्मेदार है, तो वह प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने खुलेआम अपने सांसदों को छात्रों के आंदोलन का विरोध करने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री की मंशा सही नहीं है। उन्होंने कभी भी अहम मुद्दों पर बात नहीं की है। उन्होंने आगे कहा, 'हम नियम 267 के तहत चर्चा करना चाहते थे। लेकिन सरकार इसके लिए सहमत नहीं हुई। उन्होंने राहुल, प्रियंका और अन्य लोगों का अपमान किया। हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही किसी भी चर्चा के लिए तैयार होंगे।'

यूनिवर्सिटी में पेपर लीक, दो एग्जाम हुए रद्द

उत्तराखंड। दिल्ली के जंतर-मंतर पर पेपर लीक को लेकर चल रहे धरना-प्रदर्शन के बीच उत्तराखंड में एक और पेपर लीक की खबर सामने आई है. उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के दो पेपर कथित तौर पर लीक हो गए. इसके बाद उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी दोनों सब्जेक्ट की परीक्षा रद्द कर दी है.

जानकारी के मुताबिक आरोपी शिक्षक आशीष कुमार शिवालिक कॉलेज में प्रोफेसर हैं और पेपर सेटर के रूप में प्रश्नपत्र तैयार करने का काम कर रहे थे. उन पर आरोप है कि उन्होंने परीक्षा से मिलते-जुलते सवाल एक कॉलेज के व्हाट्सऐप ग्रुप में छात्रों को भेजे. इसके बाद दोनों पेपर रद्द कर दिए गए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. इस पूरे

घटनाक्रम में कॉलेज की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. इस मामले में आरोपी शिक्षक पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है. पेपर लीक को लेकर देशभर में मौजूद माहौल के बीच ये खबर काफी ज्यादा बड़ी हो सकती है. छात्र लगातार पेपर लीक की घटनाओं को रोकने और इसकी जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे हैं. इसी बीच उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से ये खबर सामने आई है. वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर तृप्ता ठाकुर ने इस मामले को लेकर कहा कि, जिस कॉलेज से ये टीचर हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग गई है. हमने अपनी तरफ से आगामी परीक्षा की किसी भी गतिविधि में उस शिक्षक की भूमिका को अगले 7 साल के लिए रोक दिया है. इस टीचर ने अपने 22 बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज किया है. शिवालिक कॉलेज के 8 जुलाई को हुए एक पेपर को लेकर शिकायतें सामने आई थीं, जिसमें छात्रों ने आरोप लगाया था कि Machine Learning for Internet of Things सब्जेक्ट का पेपर पहले से ही छात्रों के पास आ गया था. इस पेपर के मिलते जुलते 90% सवाल, शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सहायक प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता ने परीक्षा से पहले छात्रों को व्हाट्सएप पर भेजे थे.

नीट पेपर लीक पर कटिहार में बवाल! पुलिस ने किया लाठीचार्ज

पूर्णिया। नीट पेपर लीक मामले को लेकर बिहार के कटिहार में गुरुवार को छात्रों का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा। सैकड़ों छात्र समाहरणालय पहुंच गए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई, जब प्रदर्शनकारी छात्रों ने समाहरणालय के मुख्य गेट का घेराव कर उसे तोड़ने का प्रयास किया।

इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई और पुलिस-प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, प्रदर्शन कर रहे छात्र नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान भीड़ धीरे-धीरे उग्र होती चली गई। आक्रोशित छात्रों ने समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचकर गेट को धक्का देना शुरू कर दिया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने गेट तोड़कर परिसर में प्रवेश करने की भी कोशिश की। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया। गेट के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच पहले तीखी नोकझोंक हुई, जो देखते ही देखते धक्का-मुक्की में बदल गई। हालात लगातार बिगड़ते देख पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने और समाहरणालय परिसर की सुरक्षा बनाए रखने के लिए लाठीचार्ज किया। पुलिस कार्रवाई के बाद कुछ देर के लिए भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और प्रदर्शनकारी इधर-उधर भागने लगे। लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शन और उग्र हो गया। आरोप है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल पर ईंट-पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। अचानक हुए पथराव से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा घेरा बनाकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों में भी दहशत का माहौल बन गया।

अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर हालात किए गए नियंत्रित

घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया। इसके बाद समाहरणालय परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया, ताकि दोबारा किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। घटना के बाद प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पुलिस प्रदर्शन में शामिल लोगों को पहचान करने के लिए वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है।

एसीपी और सिपाही पर नुकीली चीज से हमला, मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन बुधवार देर रात अचानक हिंसक हो गया। दिनभर शांतिपूर्ण माहौल के बाद देर रात पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी भिड़ंत हुई। इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बुधवार शाम प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई पत्थरबाजी में दो सहायक पुलिस आयुक्त और चार पुलिसकर्मी घायल हुए। उन्होंने यह भी बताया कि कई असामाजिक तत्व प्रदर्शन स्थल पर घुस आए थे। जानकारी सामने आई है कि प्रदर्शनकारियों ने सहायक पुलिस आयुक्त विवेक भगत पर नुकीली वस्तु से हमला किया। दिल्ली पुलिस के एक मुख्य आरक्षक को भी भीड़ में नुकीली वस्तु (चाकू जैसी) मारी गई। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल भी किया। इसका वीडियो सामने आया है। कल जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर नंदकिशोर ने कहा कि मैं जंतर-मंतर पर नाइट ड्यूटी पर था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मुझे गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिल रही थी। मुझे हनुमान मंदिर रोड पर एक जगह मिली; उसके बाद मैं वहां से पैदल जा रहा था। वहां बहुत सारे छात्र थे। मुझे डर नहीं लगा क्योंकि वे छात्र थे, जब मैं संसद मार्ग पहुंचा, तो वहां लगभग ढाई हजार लोगों की भीड़ थी फिर वे अचानक गुस्से में आ गए और मेरी तरफ बढ़ने लगे, यह कहते हुए कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं हम पर हमला हो रहा है... फिर उन्होंने मुझे पीछे से लात मारी और घूंसे मारने लगे। मुझ पर हमला करने वाले लगभग 150 लोग थे, एक पुलिस टीम ने मुझे बचाया। मुझे आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीनियर अधिकारी भी घायल हुए हैं, ये वे छात्र नहीं हैं जिन्होंने पुलिस की वर्दी या CRPF के जवानों को देखकर लोगों पर इस तरह हमला किया हो; वे वर्दी वालों को निशाना बना रहे हैं। ये असामाजिक तत्व हैं, जो भी वर्दी में दिखता है, चाहे वह रैपिड एक्शन फोर्स का हो, पुलिस का हो या CRPF का, उसे देखते ही पीटा जा रहा है। वहां पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया, जो भी अकेला जा रहा है, उसे वे निशाना बना रहे हैं। घटना के बाद अस्पताल अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि एक सहायक पुलिस आयुक्त को जख्म अस्पताल लाया गया था। कनॉट प्लेस के सहायक पुलिस आयुक्त विवेक भगत को डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया। उन्हें सिर में चोट और शरीर पर कई जगह खरोंचें आई थीं।

सक्षम भारत की वेबसाईड से जुड़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें।